भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2338

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

जनजातीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच

†2338. **डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, विशेषकर दूरदराज और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, जनजातीय छात्रों के बीच कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), उच्च ड्रॉपआउट दर और उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच के संबंध में कोई आकलन किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित या स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, छात्रावासों, डिजिटल शिक्षण केंद्रों और कौशल-आधारित उच्च शिक्षा सुविधाओं सहित केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय और ग्रामीण छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार हेतु अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थान, जनजातीय छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर, डिजिटल पुस्तकालय और करियर मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि करना केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है।

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2023-24 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या 7,893 है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 2.25 लाख है, जिनमें से 426 एचईआई और 19.6 हजार नामांकन महाराष्ट्र के 3 जिलों (चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया जिले) में हैं। महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2019-20 में 15.7 से बढ़कर 2023-24 में 19.1 हो गया है।

(ख) एआईएसएचई 2023-24 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में 9 केंद्र द्वारा वित्त पोषित एचईआई हैं तथा महाराष्ट्र के 3 जिलों (चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया) में 311 कॉलेज और 114 छात्रावास हैं।

महाराष्ट्र राज्य में, 39 स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) हैं, जिनमें से 9 ईएमआरएस महाराष्ट्र के 3 जिलों (चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया) में स्वीकृत/कार्यात्मक हैं।

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस(यूडाइज़+) 2025-26 के अनुसार, महाराष्ट्र के 3 जिलों (चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया) में 2 केंद्रीय विद्यालय (केवी) और 3 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) हैं।

सभी राज्यों में शिक्षा की समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

समग्र शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/वंचित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में रूसा का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान सुविधाओं, छात्रावासों, शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं के निर्माण और उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाओं सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2013 में रूसा की स्थापना के बाद से, महाराष्ट्र राज्य के लिए 1431.31 करोड़ रुपये की कुल 144 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; इसमें पीएम-उषा के तहत 814.24 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत, गढ़चिरौली-चिमूर लोकसभा

क्षेत्र में, 126.98 करोड़ रुपये की राशि के लिए 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) घटक के तहत गोंडवाना विश्वविद्यालय, गढ़चिरौली को 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और संस्थागत शासन में सुधार के लिए, वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एमईआरआईटीई (तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार) योजना को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

यूजीसी ने ग्रामीण और आदिवासी छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं; विवरण इस प्रकार हैं: -

- स्वयम् (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो स्वयम् प्लेटफॉर्म (www.swayam.gov.in) पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी अधिगम के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- यूजीसी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) पोर्टल: संग्रहीत स्वयं गैर-प्रौद्योगिकी स्नातक और स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम यूजीसी एमओओसी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- ई-पीजी पाठशाला: गैर-प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर ई-सामग्री ई-पीजी पाठशाला (https://epgp.inflibnet.ac.in/) में उपलब्ध है और छात्रों/संकाय सदस्यों/पेशेवरों/आजीवन शिक्षार्थियों के लिए एक ही स्थान पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
- यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा आकांक्षी माइंड्स के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो विश्वविद्यालयों को स्वयम् प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम के माध्यम से एक सेमेस्टर में कुल पाठ्यक्रमों का 40% तक लेने की अनुमति देता है।
- यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल: यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल को डिजिटल सेवा पोर्टल (https://digitalseva.csc.gov.in) के साथ एकीकृत किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संचालित एक मंच है, जो कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए है। इस एकीकरण के माध्यम से, छात्र डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल (http://www.ugceresources.in), यूजीसी ई-पीजी पाठशाला के तहत उपलब्ध ई-सामग्री, जो 67 स्नातकोत्तर विषयों (https://epgp.inflibnet.ac.in/) में ई-सामग्री होस्ट करता है, और यूजीसी संग्रहीत स्वयं एमओओसी पोर्टल (https://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/) शामिल हैं। यह एकीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सीएससी के माध्यम से उच्च शिक्षा ई-सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे डिजिटल

कनेक्टिविटी और अधिगम के अवसरों में सुधार होता है। इसके अलावा, यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल 27 स्वयं गैर-प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर एमओओसी की भी मेजबानी करता है, जिनका आठ क्षेत्रीय भाषाओं- हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में अनुवाद किया गया है, ताकि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बहुभाषी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जा सके।

- डीटीएच चैनल (स्वयम् प्रभा): 24/7 शैक्षिक सामग्री डायरेक्ट-टू-होम चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित होती है। यह कई विषयों में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और अध्ययन सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करता है। जीसैट-15 उपग्रह के माध्यम से नि: शुल्क उपलब्ध, स्वयं प्रभा विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो डिजिटल विभाजन को पाटता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है।

****